Fourteenth Loksabha

Session : 6
Date : 13-12-2005

Participants : Mahato Shri Sunil Kumar

>

Title : Need for early payment of pending salary, other dues of VRS to the teachers of HCL/ICCK school at Eastern Singhbhum district of Jharkhand.

श्री सुनील कुमार महतो (जमशेदपुर) : सभापति महोदय, झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में एचसीएल, आईसीसी मैनेजमैंट द्वारा श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए श्रमिक संघ से एग्रीमैंट कर प्रोप्राइटरी स्कूल 1932 से 1992 तक समय-समय पर स्थापित किए गए जिन में शिक्षक और अन्य कर्मचारी वर्ग से स्थायी पद पर कार्यरत हैं। इन स्कूलों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को सरकारी शिक्षकों के बराबर पे-स्केल एवं अन्य सुविधाएं समय-समय पर देने के लिए एचसीएल के मैनेजिंग डायरैक्टर द्वारा फाइनैंशियल अंडरटेकिंग की गई और उस आधार पर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मैनेजमैंट के स्कूलों को चलाने की स्वीकृति प्रदान की जाती रही है लेकिन सितम्बर 2002 से कम्पनी द्वारा वेतन रोक दिया गया। साथ ही साथ बहुत सारी बकाया रकम का भी भुगतान नहीं किया गया और न ही पे-स्केल रिविजन की सुविधा प्रदान की गई। 1973 एवं 1980 में राज्य सरकार द्वारा कम्पनी स्कूलों को सरकार को हैंड ओवर कर देने के कई लिखित निर्देशों को भी ठुकरा दिया गया। वे उन्हें कम्पनी के मैनेजमैंट द्वारा लिखित सूचना के माध्यम से चलाने के लिए राजी हुए। वर्तमान में मैनेजमैंट द्वारा इन स्कूलों को बंद करने की धमकी दी जा रही है।

MR. CHAIRMAN: You can give your statement here.

श्री सुनील कुमार महतो : सभापति महोदय, 25 शिक्षकों के जीवन-मरण का सवाल है। मुझे ज्ञात हुआ है कि खदानों के बंदी के चलते एचसीएल के मैनेजिंग डायरैक्टर द्वारा कम्पनी के विद्यालयों के कर्मचारियों को वीआरएस का लाभ देने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति हेतु खान मंत्रालय के पास जुलाई 2004 में ही प्रस्ताव भेजा गया था जो कि लंबित है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे 6 विद्यालयों के शिक्षकों का बकाया लंबित वेतन एवं अन्य बकाया रकम का भुगतान किया जाए।

MR. CHAIRMAN: You are not supposed to read the whole statement. This is only a Special Mention Hour.

श्री सुनील कुमार महतो : वहां अध्यापक मरने के कगार पर हैं। इसलिए यह बहुत गम्भीर मामला है। आमरण अनशन करके लोग मर रहे हैं। मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया है। आज ये लोग भूख से मर रहे हैं लेकिन

इनका बकाया सरकार नहीं दे रही cè[R68]।